विवरण

देश में चुनकर सहकारी समितियां

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्राथमिक चुनकर सहकारी समितियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	598
2.	असम	1643
3.	बिहार	1385
4.	गुजरात	1298
5.	हरियाणा	440
6.	हिमाचल प्रदेश	148
7.	जम्मू व कश्मीर	223
8.	कर्नाटक	278
9.	केरल	602
10.	मध्य प्रदेश	504
11.	महाराष्ट्र	842
12.	मणिपुर	1056
13.	उड़ीसा	756
14.	पंजाब	1127
15.	राजस्थान	636
16.	तमिलनाडु	1505
17.	त्रिपुरा	69
18.	उत्तर प्रदेश	4323
19.	पश्चिम बंगाल	1388
20.	मेघालय	28
21.	पांडिचेरी	14
22	मिजोरम	41
23.	दिल्ली	449
24.	नागालैण्ड	74
	कुल:	19,427

Sick NTC mills in Gujarat

483. SHRI ANANTRAY DEV-SHANKER DAVE : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of NTC sick textile units in Gujarat due to financial crisis and heavy losses;

(b) whether Government propose to close down these units or implementing worker's cooperative scheme to operate these sick mills;

(c) whether Government have received any proposal form the worker's cooperative to operate these mills to defuse more unemployment; and

(d) whether there is any proposal to introduce golden handshake scheme in NTC units and if so, what is workers/ employees' reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) All the 11 running mills of National Textile Corporation in Gujarat are incurring heavy losses.

(b) to (d) Government have approved a Turn Around Startegy would be selective modernisation, financial and managerial restructuring and rationalisation of surplus workforce through the Voluntary Retirement Scheme. Voluntary Retirement Scheme will also be offered to the officers, staff and workers of such chronically sick mills, which have no possibility of viability and which may have to be closed down or merged with adjacent units to ensure viability. Government is prepared to extend full support to any viable proposal for the cooperativisation of NTC mills provided it bears the consent of all parties concerned. However, no concrete proposal in this regard has been received so far. Voluntary Retirement Scheme is already in vogue in NTC. 248 officers/ staff and 10,380, workers of NTC availed of Voluntary Retirement Scheme upto 31st October, 1992 as part of the Turn around strategy.

Production and export of polyester garments

484. SHRI RAM RATAN RAM :
Dr. NAUNIHAL SINGH :

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) the polyester garments produced in Uttar Pradesh during the last three year;

(b) the garments out of the above which were exported during the last three year; and

(c) the garments which were exported to hard currency areas?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Production of garments is the small scale sector. No accurate assessment on he quantum of production of garments is therefore available.

(b) and (c) Export figures are neither monitored nor maintained on a statewise basis.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

485. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की रुग्ण मिलों के कामगारों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरु की गयी है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर 1992 तक इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति की इच्छा प्रकट करने वाले सेवा निवृत्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की श्रेणी-वार जैसे मशीनमैन लिपिकीय और प्रबंधक कर्मियों आदि की संख्या क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा दबाव डाल कर सेवानिवृत्ति के लिए बाध्य किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की संख्या क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां,

(ख) 31 अक्टूबर 1992 तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 248 अधिकारियों/कर्मचारियों तथा 10,380 कामगारों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाया है।

(ग) और (घ) एन टी सी के कर्मचारियों पर दबाव डाल कर सेवा निवृत्ति के लिए उन्हें बाध्य करने की कोई भी शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

वर्तमान धागा नीति में परिवर्तन

486. **डॉ० जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कि देश में हथकरघा उद्योग में लगे बुनकरों को सस्ते दाम पर धागा उपलब्ध करवाने के लिह सरकार वर्तमान धागा नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना असंगठित क्षेत्र के बुनकरों के लिए कोई नये प्रावधान किये गये है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है, और

(ङ) क्या यह भी सच है कि असंगठित क्षेत्र के बुनकरों की संख्या संगठित क्षेत्र के बुनकरों से ज्यादा है, यदि हां, तो उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र में सूत की आपूर्ति के लिए कार्यान्वित योजनाओं की सरकार समय-समय पर समीक्षा करती है। मिल-गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की एक संशोधित योजना अभी हाल ही में आरंभ की गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के तत्वावधान में कार्यान्वित मिल-गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की योजना में कहा गया है कि राज्य हथकरघा अभिकरणों जैसे राज्य हथकरघा विकास निगम और राज्य शीर्ष-क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों में पंजीकृत बुनकरों की सूत की आपूर्ति की जाए। इस योजना में राज्य हथकरघा अभिकरणों में अंतर्गत शामिल व्यक्तिगत बुनकरों को भी शामिल किया गया है। अपर्याप्त संगठनात्मक व्यवस्था और सूत आपूर्ति की प्रणाली में लीकेज़ होने की संभावना को देखते हुए प्राइवेट क्षेत्र के बुनकरों को इस योजना में शामिल करना संभव नहीं है।

(ङ) वर्ष 1987-88 में की गई राष्ट्रीय हथकरघा गणना के अनुसार देश में 22.43 लाख पूर्णकालिक बुनकर हैं जिसमें से 12.11 लाख बुनकर स्वतंत्र बुनकर हैं और 3.45 लाख मास्टर बुनकर के अंतर्गत हैं।